बजट के बारे में

- 'बजट' शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के 'बूजट' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला. दरअसल, उस जमाने में अंग्रेज चमड़े के थैलों में लेखा-जोखा रखते थे. भारतीय संविधान में केंद्रीय बजट को बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है. वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है.
- सामान्य तौर पर बजट साल में एक बार पेश होता है, जिसे आम बजट कहते हैं. यह एक वित्त वर्ष के लिए होता है. संविधान के मुताबिक, केंद्र सरकार वित्त वर्ष के अलावा आंशिक समय के लिए भी बजट पेश कर सकती है, जिसे अंतरिम बजट कहते हैं. आम तौर पर अंतरिम बजट चुनावी साल में पेश होता है. अंतरिम बजट में सरकार नीतिगत फैसले लेने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं होती. अंतरिम बजट को लेखानुदान भी कहा जाता है.
- अंतरिम बजट और लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) में थोड़ा अंतर है. केंद्र सरकार आंशिक समय के लिए संसद से खर्चों के लिए अनुमति मांगती है, तो वह केवल लेखानुदान पेश कर सकती है. अंतरिम बजट में खर्च के साथ राजस्व का ब्यौरा भी देना होता है, जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्चों के लिए संसद से मंजूरी लेनी होती है.
- आजाद भारत का सबसे पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था.

बजट के प्रभाव

कम होगा जनता का विश्वास

यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट ही कहा जायेगा. लेकिन, यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट का गणित सही नहीं है. कई चीजों में छूट दी गयी है, जिसके लिए सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा, मसलन किसानों के लिए 75 हजार करोड़ रुपये बजट रखा गया है, तो यह पैसा कहां से आयेगा. सरकार ने बजट में जितने भी वादे किये हैं, उनको पूरा करने में इतना पैसा खर्च होगा कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ जायेगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. अभी जो राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत है, वह चार प्रतिशत के करीब पहुंच जायेगा. दूसरी बात यह है कि जब एक अप्रैल से अगला वित्त वर्ष शुरू होगा, तब बजट में किये गये सारे वादों को पूरा करने के लिए जब तक क्रियान्वयन शुरू होगा, तब तक नयी सरकार आ जायेगी. अब नयी सरकार इन योजनाओं को आगे बढ़ायेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है. बीते सालों में सरकार ने कई ऐसे वादे किये, जो पूरे नहीं हो पाये. ऐसे में सरकार के दोबारा किये गये इन वादों से जनता का विश्वास कम होगा. जनता के मन में यह बात गहरी बैठ जायेगी कि ये लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते. इस स्थिति के चलते इस लोकलुभावन और चुनावी बजट का कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा.

प्रो अरुण कुमार
अर्थशास्त्री

बीते सालों में सरकार ने कई ऐसे वादे किये, जो पूरे नहीं हो पाये. ऐसे में सरकार के दोबारा किये गये इन वादों से जनता का विश्वास कम होगा.

किसानों की प्रतिक्रिया भी आयी है कि सालाना छह हजार तो कुछ भी नहीं है. दूसरी बात यह है कि छह हजार का ऐलान तो हो गया, लेकिन यह कबसे और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ऐसे ही सवाल बाकी चीजों के बजट को लेकर भी है, जो जनता के मन में उठ रहे हैं. इसलिए इसमें दो राय नहीं कि इस बजट का कोई राजनीतिक फायदा नहीं होनेवाला है, जितना कि सरकार सोच रही है. क्योंकि, ऐसे वादों के लिए बहुत देर हो चुकी है और चुनाव हम सबके सामने है. रोजगार सृजन को लेकर क्या योजना है, इसकी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है. एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ ऐलान जरूर हुए हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन पर अस्पष्टता है.

वैसे तो बजट बहुत पहले से तैयार किया जाता है और इसकी एक खास प्रक्रिया भी है. लेकिन, ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबों के लिए न्यूनतम आय की व्यवस्था करेंगे, तो इस सरकार में बैठे लोगों ने सोचा कि इस बजट में जनता के लिए हम भी कुछ करेंगे. और इस तरह पूरा बजट चुनावी बजट बना दिया गया. यही वजह है कि इसका गणित सही नहीं दिख रहा है. कुछ चीजें तो ऐसे ही ऐलान कर दी गयी हैं कि आगे चलके उसका क्रियान्वयन कर देंगे. दरअसल, अगर इनको यह लगता कि अगली सरकार भी इन्हीं की बनेगी, तो ये लोग इतने वादे नहीं किये होते. इन्हें विश्वास ही नहीं है कि अगली सरकार इनकी बनेगी, इसलिए इन्होंने लोकलुभावन बजट बना दिया है. सरकार ऐसा करने से बच सकती थी.

(बातचीत : वसीम अकरम)

फायदे | मिडिल क्लास को लाभ

राजनीतिक रूप से स्मार्ट बजट है

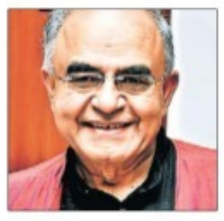

गुरचरण दास
कॉरपोरेट एक्सपर्ट

पहली बार किसी केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों, दुकानों, खेतों, दूसरों के घरों जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों और छोटी-छोटी जगहों पर काम करनेवाले मजदूर, जो महीने में 15 हजार से कम कमाते हैं, उनके लिए पेंशन शुरू की है.

राजनीतिक रूप से यह बहुत अच्छा व स्मार्ट बजट है, लेकिन कहीं से भी यह बजट लोकलुभावन नहीं है. आम तौर पर सरकारें बजट के माध्यम से प्रचार करती हैं कि हमने ये दिया-वो दिया, लेकिन यह बजट ऐसा नहीं है. इसमें सरकार की राजकोषीय नजरिये से जिम्मेदारी दिखायी देती है. इस वित्त वर्ष (2019) राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 ही रहनेवाला है. पिछले बजट में यह आंकड़ा 3.3 प्रतिशत का था. यानी मात्र 0.1 प्रतिशत ही वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी दर्ज की जायेगी.

चुनावी बजट होने के लिहाज से भी यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए समझदार बजट कहा जायेगा. बजट प्रस्तुत होने के बाद अर्थशास्त्री आम तौर पर इन पहलुओं पर नजर रखते हैं कि सरकार ने जो बड़े-बड़े वादे जनता से किये हैं, उनकी पूर्ति के लिए पैसा कहां से आयेगा. ऐसा बजट बहुत गैरजिम्मेदार माना जाता है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और बजट में सारे आर्थिक पक्षों का खयाल किया गया है. मुख्यतः तीन बातें हैं, जिनका यहां उल्लेख करना जरूरी है. पहली तो यह कि इस बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने जा रही है. ढाई लाख से बढ़ाकर, अब पांच लाख तक के वेतन पानेवाले लोगों को इनकम टैक्स की छूट रहेगी. अगर वह व्यक्ति सरकारी मदों में निवेश करता है, तो उसकी 6.5 लाख तक की कमाई भी इनकम टैक्स के अंतर्गत नहीं आयेगी. अभी तक ज्यादा असंतोष मिडिल क्लास में दिख रहा था. इस कदम ने मिडिल क्लास का दिल जीत लिया है और छोटे व्यापारियों को भी इससे राहत मिलेगी.

दूसरी बात है कि पहली बार किसी केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों, दुकानों, खेतों, दूसरों के घरों जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों, छोटी-छोटी जगहों पर काम करनेवाले मजदूर, जो 15 हजार रुपये महीने से कम कमाते हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम शुरू की है. देश के लगभग 90 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. पेंशन स्कीम से इन्हें बहुत फायदा होगा. इन मजदूरों को 100 रुपया महीना जमा करते रहना होगा और जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हो जायेगी, तो उन्हें 3,000 रुपये महीना मिलना शुरू जायेगा.

तीसरी प्रमुख बात यह है कि दो हेक्टेयर से कम जमीनों के मालिक छोटे किसानों को साल में 6000 रुपये सीधे कैश ट्रांसफर से प्रदान किये जायेंगे. देखा जाये, तो यह राशि बहुत कम हैं, लेकिन यह इसे एक शुरुआत माननी चाहिए. इससे पहले ऐसे कदम नहीं उठाये गये थे. हालांकि, इस पर 75 हजार करोड़ का खर्च आयेगा और इसके लिए अन्य अनावश्यक कृषि संबंधी सब्सिडियों को बंद करके खर्च जुटाया जा सकता है. कुल मिलाकर, यह बजट पॉलिटिकली स्मार्ट है, बड़ी जिम्मेदारी से पेश किया गया है और लोकलुभावन नहीं है.

(बातचीत : देवेश)

घोषणाएं | इंडस्ट्रीज को लेकर घोषणा नहीं

रोजगार और विकास से ज्यादा चुनाव को तवज्जो

अरविंद मोहन
अर्थशास्त्री

विकासोन्मुख बजट नहीं होने से वित्तीय स्वास्थ्य और खराब ही होगा. इससे आनेवाली नयी सरकार के लिए बहुत बड़ा दबाव होगा. जिस प्रकार घोषणाएं की गयी हैं, उससे नयी सरकार को पीछे जाने में मुश्किलें आयेंगी.

यह बजट से ज्यादा चुनावी अभियान की शुरुआत है. मौटे तौर पर हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गयी है. बजट में कुछ घोषणाएं अच्छी भी हैं. खेती-किसानी की हालत लगातार खराब हो रही है. कृषि को प्रत्यक्ष लाभ के तहत सालाना 6000 रुपये देने की घोषणा की गयी है. अगर यह योजना दो वर्ष पहले आयी होती, तो यह एक अच्छा फैसला हो सकता था. मध्यम वर्ग के लिए आयकर सीमा को पांच लाख करने के साथ-साथ हाउसिंग सेक्टर को राहत देने का प्रयास किया गया है. पूंजीगत लाभ कर में राहत देने के साथ दूसरा घर खरीदनेवालों के लिए प्रकल्पित कर (प्रिज्मटिव टैक्स) हटा दिया गया है. घर खरीद के लिए जीएसटी कम करने हेतु मंत्री समूह बनाने की घोषणा की गयी है. साथ ही नयी पेंशन योजना में सरकार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गयी है. अगर इन सभी घोषणाओं को देखें, तो एक साथ मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग को साधने की कोशिश की गयी है.

यहां पूरे बजट को दो पहलुओं में देखना चाहिए, पहला यह कि राजकोषीय संतुलन के लिहाज से देखें, तो देश में 2003 में एफआरबीएम एक्ट आने के बाद से एक राजकोषीय संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है. यहां यह समझना मुश्किल है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि किसानों के लिए एक झटके में 75 हजार करोड़ की स्कीम ले आयें, तीन करोड़ लोगों को टैक्स नेट से बाहर कर दें, कैपिटल गेन और जीएसटी दर को भी कम कर दें. यानी एक तरफ कर संग्रह को नीचे ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ खर्च बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं. पहले से चल रहा आयुष्मान भारत अगर ढंग से लागू किया जाता है, तो खर्च बढ़ेगा ही. राजकोषीय संतुलन कैसे सधेगा, यह बजट से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है.

वित्त मंत्री ने कहा है कि 2019-20 में राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत रखेंगे, लेकिन बजट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई गंभीर पहल हुई है. वित्त मंत्री को मालूम है कि तकनीकी रूप से यह 'वोट ऑन अकाउंट' बजट है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अब तीन महीने ही बचा है. इसके बाद नयी सरकार अपना बजट लेकर आयेगी और वही बजट लागू होगा. जितने भी फैसले हैं, चाहे आयकर सीमा में छूट हो या पूंजीगत लाभ कर कम करने की बात हो, यह कुछ भी लागू होने नहीं जा रहा है. अगर सभी घोषणाओं पर एक साथ पहल होती है, तो राजकोषीय संतुलन बनाना मुश्किल हो जायेगा. दूसरा सच है कि देश में किसानों के लिए सपोर्ट सिस्टम और सामाजिक सुरक्षा की सख्त कमी है. चाहे वह पेंशन योजना हो या किसानों के लिए किसी प्रकार की मदद, वह बेहद जरूरी है. लेकिन, इस प्रकार की घोषणाओं का यह समय बिल्कुल गलत है. इससे स्पष्ट है कि समाधान के प्रति गंभीरता कम है. दूसरे, सुधार के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन विकास को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण इस बजट में नहीं दिख रहा है.

किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए नये सिरे से काम करने की जरूरत है. चुनावों में किसान और मध्य वर्ग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. कृषि वाले प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में बेहतर प्रदर्शन किये बगैर किसी पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं बन सकती. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस बजट को चुनावी घोषणा की तरह पेश किया गया है. यहां फील गुड कराने की कोशिश की गयी है.

वर्तमान में रोजगार का मसला बहुत बड़ा है. रोजगार पैदा करने के मामले में न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं. रोजगार का बढ़ना तभी संभव है, जब विकास को गति दे पायेंगे. खास बात है कि इस बजट में उस दिशा में कोई प्रयास होता नहीं दिखा. अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और किसानों की निश्चित आमदनी, जिसके लिए बार-बार कहा जाता है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्रयास होता नहीं दिखा है.

विकासोन्मुख बजट नहीं होने से वित्तीय स्वास्थ्य और खराब ही होगा. इससे आनेवाली नयी सरकार के लिए बहुत बड़ा दबाव होगा. जिस प्रकार घोषणाएं की गयी हैं, उससे नयी सरकार को पीछे जाने में मुश्किलें आयेंगी. इस बजट में इंडस्ट्री के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं है. हालांकि, कैपिटल गेन और जीएसटी को कम करने से हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलेगी. अगर यह सेक्टर पटरी पर लौटता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. मेगासिटी में तमाम फ्लैट्स खड़े हैं, आज उनका कोई खरीदार नहीं है. अगर इस शुरुआत को एक पैकेज के रूप में सरकार आगे ले जाती है, तो निश्चित ही हाउसिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है. हाउसिंग सेक्टर की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि इससे जुड़े क्षेत्र सीमेंट, स्टील आदि को भी लाभ मिलता है. इंडस्ट्री या स्टार्ट अप के लिए कुछ भी नया नहीं हुआ है. अगर हम केवल घोषणाओं पर जायें, तो मध्यम वर्ग को खुश किया गया है. लेकिन, इनका कोई मतलब नहीं है. योजनाएं नये बजट से लागू होंगी, जो कि नयी सरकार पर निर्भर करेगा.

(बातचीत : ब्रह्मानंद मिश्र)

सरकार को सिर्फ गौमाता की चिंता है या की गोपालक किसान की भी? आवारा पशुओं की समस्या से पीड़ित किसान के लिए भी कोई योजना क्यों नहीं?

डूबते को तिनके का सहारा

योगेंद्र यादव
अध्यक्ष, स्वराज इंडिया

हर साल की तरह इस बार भी मैं किसानों और किसान कार्यकर्ता साथियों के साथ बजट सुनने और अपनी प्रतिक्रिया सुनाने के लिए एक गांव में बैठा था. गांव की महिला जानना चाहती थी कि सरकार ने ऐसी क्या घोषणा कर दी है, जिस पर टीवी वाले मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? मैंने बताया कि सरकार उनके परिवार को सम्मान के लिए सालाना 6,000 यानी हर महीने 500 रुपये देगी. शॉल के कोने को मुंह में दबाये वह हंसी और सरकार को ही 500 देने के उसके प्रस्ताव ने सरकारी दावे की कलई खोल दी. उस महिला ने कहा था- 'भाई 500 रुपये की पिनाल्टी तो सरकार हम पर लगा दे, हम ही भर देंगे.' यह थी मोदी सरकार की नवीनतम व एक और 'ऐतिहासिक' 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' पर एक किसान महिला की पहली प्रतिक्रिया.

टीवी एंकर पूछ रहे थे 'चलिये कुछ तो किसान को मिला. क्या इसे सही दिशा में छोटा कदम ही माने? और कुछ नहीं तो डूबते को तिनके का सहारा ही सही.' काश मैं उनसे सहमत हो पाता. अगर सरकार ने यह कदम अपने आप पहले एक-दो साल में उठा लिया होता, धीरे-धीरे राशि बढ़ाने का वादा किया होता, तो यही मेरी प्रतिक्रिया होती. लेकिन, पांच साल के छठे बजट में चुनावी हार का सामना कर रही सरकार द्वारा फेंके अंतिम पासे के बारे में यह राय नहीं बनायी जा सकती, आखिर पूजा में मिली धोती और भागते भूत की लंगोटी में अंतर तो है ना. डूबते को तिनके का सहारा वाली बात कुछ सही है, लेकिन यहां डूबते का मतलब किसान नहीं, बल्कि मोदी सरकार है.

इस घोषणा में सम्मान से ज्यादा अपमान सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसकी राशि ऊंट के मुंह में जीरा है. असली बात इसकी राजनीतिक नीयत है. मोदी जी को लगता है कि चला-चली की बेला में किसान परिवार की झोली में कुछ फेंककर उसका वोट झटका जा सकता है. इसलिए इस योजना को किसी सामान्य बजट कि योजना की तरह नये वित्तीय वर्ष में मार्च से नहीं, बल्कि पिछले दिसंबर से लागू किया जायेगा. इरादा साफ है कि अप्रैल-मई में चुनाव से पहले किसी तरह देश के कुछ करोड़ किसान परिवारों के बैंक के अकाउंट में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंचा दी जाये. प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं कि किसान का वोट खरीदा जा सकता है.

'चलिये सौदा ही मान लीजिए, सवाल यह है कि किसान पट जायेगा या नहीं. आखिर तेलंगाना सरकार ने भी तो ऐसा ही सौदे के बल पर चुनाव जीत लिया था?' मैंने समझाया कि तेलंगाना का मामला दूसरा था. वहां सरकार ने 'रायतु बंधु' योजना के तहत किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता दी थी, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष कर दिया गया है यानी कि पांच एकड़ वाले किसान को 50,000 सरकारी सहायता मिलती. दूसरा, वहां सरकार ने इस योजना को चुनाव से डेढ़ साल पहले लागू करना शुरू कर दिया था. लेकिन, सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह सौदा वह सरकार कर रही है, जिसकी छवि पहले से ही किसान विरोधी होने की बन चुकी है. चार साल तक किसानों की उपेक्षा, प्राकृतिक आपदा के समय बेरुखी, फसल की बिक्री में किसान की लूट और ऊपर से नोट बंदी की मार के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार जब सौदा करने की कोशिश करती है, तो वह किसान को अपने सम्मान का सौदा लगता है.

अब आखिरी सवाल मेरा इंतजार कर रहा था. 'तो फिर आप के हिसाब से सरकार को इस बजट में किसान के लिए क्या घोषणा करनी चाहिए थी?' मेरे हिसाब से सरकार को इस बजट में कोई नयी घोषणा करनी ही नहीं चाहिए थी. लोकतंत्र का कायदा है कि सरकार को पांच साल का राज मिला है. वह पांच बजट पेश कर चुकी है. छठवां बजट केवल लेखानुदान का बजट होता है. इसलिए कायदे से इस साल सरकार को लेखानुदान के साथ अपने पिछले पांच साल के काम का विस्तृत आउटकम बजट पेश करना चाहिए था.

ईमानदार होती तो सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए था, जो देशभर के किसान पूछ रहे हैं: सरकार ने घोषणा की थी कि छह साल में किसान की आमदनी को दोगुना कर दिया जायेगा. अब उसकी आधी अवधि बीतने पर किसान की आमदनी कितनी बढ़ी है? ताम-झाम के साथ प्रधानमंत्री आशा के नाम से शुरू हुई योजना के तहत किसानों के दाने-दाने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के वादे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आनेवाले किसानों की संख्या बढ़ने के बजाय घट क्यों रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा किसानों को मिला या प्राइवेट बीमा कंपनियों को? सरकार को सिर्फ गौमाता की चिंता है या की गोपालक किसान की भी? आवारा पशुओं की समस्या से पीड़ित किसान के लिए भी कोई योजना क्यों नहीं? पिछले दो साल से सरकार किसान आत्महत्या के आंकड़ों को दबाकर क्यों बैठी हुई है? इनमें से एक भी सवाल का जवाब वित्त मंत्री ने क्यों नहीं दिया?

मैं सवाल पूछते जा रहा था कि पीछे से हमारे साथी नारा लगा रहे थे- 'जुमले नहीं जवाब चाहिए, पांच साल का हिसाब चाहिए!'

फाइनल बजट तो लोकसभा चुनावों के बाद आनेवाली सरकार ही पेश करेगी. अगर भाजपा को बजट पेश करने का मौका मिला, तो निश्चय ही ये घोषणाएं फाइनल ही होंगी.

आनेवाले दिन का ट्रेलर है यह

आलोक पुराणिक
आर्थिक मामलों के जानकार

असंगठित क्षेत्र के करीब दस करोड़ कामगार, करीब 12 करोड़ छोटे किसानों का भला- ऐसी बातें अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल अपने 2019-20 के बजट भाषण में करते दिखे. सूट-बूट की सरकार, अंबानी-अडानी की सरकार जैसे आरोपों में घिरे होने के बाद, हाल में हिंदी भाषी क्षेत्रों के तीन महत्वपूर्ण राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद केंद्र सरकार एकदम से जनप्रिय, किसान प्रिय, मजदूर प्रिय दिख रही है. ऐसा होने की ठोस वजहें हैं, ठीक सामने ही लोकसभा चुनाव हैं. कुल मिलाकर इस बजट की घोषणाएं उन वर्गों, उन लोगों को हाशिये से केंद्र में लाती हुई दिख रही हैं, जिनके पास वोट हैं, सरकार बदलने की ताकत है.

जय किसान, हो मेहरबान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर तक जमीन रखनेवालों को किसानों को साल में छह हजार रुपये दिये जायेंगे. करीब बारह करोड़ किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलने की उम्मीद है. किसानों को इस स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इतनी तत्पर है कि दिसंबर 2018 से लागू की जायेगी. यह बात बताते हुए पीयूष गोयल यह भी याद कराना नहीं भूले कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी. किसानों के राजनीतिक महत्व को हाल के वक्त में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव समझ चुके हैं. उनकी रैयत बंधु स्कीम के तहत भी किसानों के खाते में रकम ट्रांस्फर की जाती है. किसान के खाते में सीधे रकम जाये, तो बीच में लूटपाट का खतरा खत्म हो जाता है. साल में छह हजार रुपये से किसानों का कितना भला और कितना दीर्घजीवी उद्धार होगा, यह तो आगे देखा जायेगा. पर यह बात साफ होती है कि हाल की चुनावी हारों और 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के खराब प्रदर्शन से केंद्र सरकार को समझ में आया कि किसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाना जरूरी है, जो उन्हें भी होता हुए दिखे.

पेंशन कामगारों के लिए

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फिक्र दिखायी है. घोषणाओं के मुताबिक दस करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को तीन हजार प्रति माह की पेंशन मिलेगी, अगर असंगठित कामगार 18 साल की उम्र में पेंशन स्कीम में आकर सिर्फ 55 रुपये प्रति माह का भुगतान करें या 29 साल की उम्र में पेंशन स्कीम में आकर सिर्फ 100 रुपये प्रति माह का भुगतान करें. दरअसल, अब अर्थव्यवस्था में एक प्रवृत्ति साफ तौर पर देखने में आ रही है. वह यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, तो काम करने के लिए लोगों की जरूरत है. नौकरियां हैं पर पक्की नहीं हैं. ऐसी सूरत में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था को लेकर भारी चिंताएं हैं. यह स्कीम एक हद तक उन चिंताओं को दूर सकती है. जाहिर है आगामी चुनावी भाषणों में किसान और मजदूर प्रिय होने का दावा भाजपा कर पाये, ऐसे इंतजाम इस बजट में कर लिये गये हैं.

मुखर मध्य वर्ग प्लीज शांत

मध्य वर्ग की चिंता हर बजट के बाद यही रहती है कि उसकी आय में से कितना कर जानेवाला है. हाल के बरसों में तनख्वाहें लगातार बढ़ी थीं, पर सरकार बजट में वेतनभोगी वर्ग को आम तौर पर राहत देने के लिए तैयार नहीं दिखती थी. बल्कि एक बजट के बाद साक्षात्कार में वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान का आशय यह था कि मध्यवर्ग को अपने आप ही खुद को संभालना चाहिए, सरकार से राहतों की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. इस बार अंतरिम वित्तमंत्री वेतनभोगी मध्यवर्ग की सुनी है. कर योग्य आय की सीमा बढ़ाकर पांच लाख हुई है, यानी अब पांच लाख रुपये तक की आमदनी कर मुक्त होगी और कर बचत करनेवाले छह लाख पचास हजार रुपये की आमदनी कर मुक्त रख पायेंगे. पांच लाख रुपये सालाना आय का मतलब करीब 42 हजार रुपये प्रति माह कमानेवाले भी कर-मुक्त रह पायेंगे. मुखर मध्यवर्ग के लिए यह खासी राहत है और सरकार के लिए भी. मुखर मध्यवर्ग की आवाज मीडिया में जल्दी और ज्यादा जगह पा जाती है.

ट्रेलर के बाद की फिल्म

कुल मिलाकर ये सारी घोषणाएं बतौर ट्रेलर ही देखी जानी चाहिए, क्योंकि फाइनल बजट तो लोकसभा चुनावों के बाद आनेवाली सरकार ही पेश करेगी. अगर भाजपा को बजट पेश करने का मौका मिला, तो निश्चय ही ये घोषणाएं फाइनल ही होंगी. अगर कोई और पार्टी बजट पेश करती है, तो भी साफ है कि किसानों, मजदूरों और मध्यवर्ग के लिए जो भी घोषणाएं हुई हैं, उन्हे वापस लेने का साहस किसी पार्टी में नहीं होगा. क्योंकि भाजपा तब एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इन्हें वापस लेना आसान नहीं होने देगी. कुल मिलाकर किसान, मध्यवर्ग और असंगठित क्षेत्र के मजदूर कुछ हासिल करने की उम्मीद बांध सकते हैं.

कमेंट

यह बजट देश को दिशा देनेवाला है

यह केवल चुनावी ही नहीं, बल्कि एक दिशा देनेवाला बजट भी है. इसमें किफायती आवास के लिए लाभ की घोषणा की गयी है और यह अच्छा कदम है.

निरंजन हीरानंदानी, सह-संस्थापक व प्रबंध निदेशक, हीरानंदानी ग्रुप

नियंत्रित व प्रोत्साहित करनेवाला

अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाले बिना जिस तरह बजट में प्रमुख मध्यम वर्ग और किसानों को राहत दी गयी है, मैं उसके लिए आभारी हूं. यह एक नियंत्रित और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देनेवाला (पंप प्राइमिंग एक्सरसाइज) कदम है.

आनंद महिंद्रा, बिजनेसमैन

कई घोषणाओं से बढ़ेगा परिव्यय

इस बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए किसी भी नयी नीति की घोषणा नहीं की गयी है, जबकि खर्चे के कई तरीकों की घोषणा की गयी है, जिससे परिव्यय बढ़ेगा और सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता पर दबाव पड़ेगा.

जेन फैंग, एएमडी, सॉवरेन रिस्क ग्रुप, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस

किसानों के साथ विश्वासघात

किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने की घोषणा वास्तव में लॉलीपॉप से भी बदतर है. यह भारत के किसानों के साथ विश्वासघात है. सरकार ने 2014 में जो वादा किया था, वह लगभग पांच वर्षों तक पूरा नहीं किया गया.

डॉ अशोक धावले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा